□□□□□ □□□□

जनसत्ता 01 जुलाई, 2014 : अयोध्या की □ कमस्जदि में पैसठ वर्ष पूर्व रामलला के प्राक्ट्य और बाबरी मस्जदि ध्वंस के बाईस वर्षों बाद अब सुरक्षा के न□ प्रबंधों में इसे 'नो फ्लाइंग जोन' में शामलि कयिा जाना है क्योंकि अब खतरा धरती से अधकि आकाश से संभावति है□ यह पता नहीं कि इसका दोष कसि देशी, वदिेशी या अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को दयिा जा□, जसिके फलस्वरूप अब न□ सुरक्षा-प्रबंध की जरूरत प□ गई है□ अयोध्या राम जन्मभूमि के अधवक्ता और सरकार द्वारा नयिुक्त पुजारी सत्येंद्र दास, जो बीस से अधकि वर्षों से सेवारत हैं, संस्कृत वद्यिालय के शक्षिक और रामलला के अर्चक अब अपनी नौकरी से सेवामुक्त हो ग□ हैं लेकनि उन्हें भी यह सब कुछ अजूबा-सा लगता है□

छह दसिंबर 1992 को मस्जदि वध्वंस के बाद अस्थायी मंदरि नरि्माण के इतहिास का तत्कालीन वरषि्ठ पुलसि अधीक्षक डीवी राय को आधार माना जा□ तो उनके द्वारा इस घटना के प्रकाशति तथ्यों और पुस्तक में यही बताया गया है कि जब वे दूसरे दनि वध्वंस स्थल पर पहुंचे तो वहां पुलसिकर्मयिों की, जो सादे वस्त्रों में थे, भी□ लगी थी□ पुलसि अधीक्षक का वांछति सम्मान करने के बाद उनका कहना था कि कल तो हम सरकारी दायत्वि का नरि्वाह कर रहे थे लेकनि आज वैयक्तकि आस्था के अनुसार मंदरि नरि्माण और उसके लि□ आरि्थक सहायता में योगदान कर रहे हैं, भला वैयक्तकि आस्था से हमको कैसे रोका जा सकता है□

यानी सरकारी सेवारत कर्मचारी के लि□ इस मामले में वैयक्तकि आस्था का नरि्वाह सर्वोपरि है, भले ही इतहिास की इस बात को भुला दयिा जा□ कि रामलला के प्राक्ट्य के लि□ तत्कालीन जलिा मजस्ट्रिेट गुरुदत्त सहि को ही अगुआ माना गया है□ □ कतो तीसरे दनि ही सेवाकाल समाप्त होने के कारण सेवामुक्त हो ग□ थे, और दूसरे, जन्हिें जलिा मजस्ट्रिेट के आरोपपत्र और जांच के बाद सरकार ने सेवामुक्त कर दयिा था□ लेकनि वे इसी सेवा के बल पर तत्कालीन भारतीय जनसंघ के टक्कि पर बहराइच से पत्नी सहति सांसद चुने ग□ थे□ पहला चुनाव तो ड्राइवर राम गरीब के साथ बस्ती से ल□, लेकनि दलति कोटे में ड्राइवर तो नरि्वाचति हो गया पर वे थो□ वोटों से पछि□ ग□ थे□ इसी प्रकार बाबरी मस्जदि वध्वंस के अभयिुक्तों की सूची में फैजाबाद के तत्कालीन वरषि्ठ पुलसि अधीक्षक डीवी राय और जलिाधकिारी रवींद्रनाथ श्रीवास्तव दोनों ही हैं□ वरषि्ठ पुलसि अधीक्षक भाजपा के सदस्य के रूप में सुलतानपुर से सांसद भी चुने ग□ थे लेकनि दूसरे चुनाव में वे भाजपा के नहीं बल्कि 'स्वतंत्र रामभक्त' के रूप में चुनाव ल□ और हारे; मुकदमे के दौरान मृत्यु के कारण अब उनका नाम अभयिुक्तों की सूची में नहीं है□

इस मामले में सरकारी अधकिारयिों और कर्मचारयिों का कतिना योगदान रहा है और जसिे श्रद्धा, आस्था कहते हैं उस रूप में कतिने जु□ हैं अगर इसे जानना हो तो ववािदति स्थल का दर्शन करने वालों की सूची पर्याप्त है जसिमें सपिाही से लेकर पुलसि महानदिेशक और कार्यपालकि के शीर्ष अधकिारयिों तक के नाम मलिेंगे□ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रद्धावनत दर्शन करने वालों में मलि जा□'गे□ सुरक्षाबलों में थल, वायु और नौसेना के कतिने अधकिारी हैं जनिकी चंता यहां वशिाल राममंदरि देखने की है□ जनि अधकिारयिों को वशिषि्ट दर्शन की व्यवस्था प्रशासन ने कराई है उस सूची में उनके नाम भी प्रमुख रूप से अंकति होंगे□

हालत तो यहां तक है कि कुछ ब□ पुलसि अधकिारी भी, यही कहते हैं कि मुकदमा चाहे जहां हो, सुनवाई चाहे जो करे, लेकनि रामलला वरिाजमान को अपनी जगह से हटाने में कोई सक्षम नहीं है□ यानी न्यायपालकि को नरि्धारति मान्यताओं और वधियिों के आधार पर कार्य करने में वे सक्षम नहीं मानते□

मगर □कही धर्म के मानने वाले देश इराक के तीन भागों में विघटन की संभावना□ं यह भी बताती हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं□ इसे देश की कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संवैधानिक आस्था का प्रतीक मानें या उसके विपरीत, यह आपकी मर्जी है□ तर्क यही है कि इस मामले में आस्था की ही जीत होगी- तथ्य, साक्ष्य, इतिहास की नहीं□ इस संबंध में अब तक जो शोध प्रकाशित हैं वे भी इसके पक्के गवाह नहीं माने जा सकते□

रामलला के प्राकट्य से लेकर 1984 तक अयोध्या में इसकी देखरेख और सुरक्षा का दायित्व पतला डंडा लि□ थाने का □क ऐसा सिपाही निभाता था जिसका अन्य स्थानों पर कोई ब□ा उपयोग नहीं किया जा सकता था□ लेकिन इस बीच ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जब आस्था, विरोध और विद्वेष के कारण इस मूर्ति को हटाने की आवश्यकता प□ी हो, हां यह अवश्य देखा जा सकता है कि 23-24 नवंबर 1949 को प्राकट्य तो केवल रामलला विराजमान का बताया जाता है लेकिन वहां भरत, शत्रुघ्न और हनुमानजी की मूर्तियां कब प्रकट हो गर्इं इसका कोई उल्लेख नहीं□

हां अब अस्थायी मंदिर में उन्हें अवश्य देखा जा सकता है□ इस स्थल में अखबार वालों के कागज-कलम भी इसलि□ रखवा लि□ जाते थे क्योंकि उनसे सुरक्षा को खतरा हो सकता है□ लेकिन वहां जिलाधिकारी केके नैयर, सिटी मजिस्ट्रेट और इस आंदोलन के नायक रामचंद्र दास परमहंस के तीन-तीन फीट के ब□ फोटोग्राफ कैसे पहुंच ग□ यह सरकारी जानकारियों में उपलब्ध नहीं है□

अब सवाल उठता है कि आखिर मस्जिद के अस्तित्वहीन होने के बाद रामलला विराजमान को खतरा किन कारणों से या किन तत्त्वों के द्वारा संभावित है, वे देशी हैं या विदेशी? जब विमान की उ□ानों को भी हम अदृश्य खतरों में शामिल कर लेते हैं तो यही लगता है कि यह वास्तव में उसी प्रकार का तो नहीं जैसे कुछ लोग इस तरह की कल्पना□ं प्रचारित करते रहते हैं कि अब सृष्टि का विनाश होने वाला है या अमुक देश का अमुक भाग समाप्त होने वाला है या किसी क्षेत्र में महाप्रलय जैसी स्थिति आ□गी और कुछ भी नहीं बच पा□गा□ यह बात दूसरी है कि ये सारी आस्थाजनित भविष्यवाणियां कहीं भी सत्य नहीं सिद्ध हुई हैं□ लेकिन जब सुरक्षा के उपाय करने ही हैं तो अतिरिक्त प्रयत्नों से □तराज क्या!

हवाईखतरे की सूचना□ं किन आधारभूत साक्ष्यों और सामग्रियों पर आधारित हैं इसे पूछना भी क्या पता रामलला में अनास्था का परिचायक कहा जा□□ लेकिन जब इस विवाद के इतिहास को देखा जा□गा और गुप्तचर □जेंसी के द्वारा दी गई रिपोर्ट इस संबंध में कितने भ्रमों और कितनी वास्तविकताओं का पर्याय रही है इसका विवेचन किया जा□गा, तो फैला□ ग□ भ्रमों की संख्या, जो इस आंदोलन को ब□ाने में सहायक थी, कई गुना अधिक मिलेगी□ यही कारण है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब अस्थायी मंदिर का निर्माण हो रहा था, प्रधानमंत्री सचिवालय के पास भी यही रिपोर्ट थी कि अगर इसमें व्यवधान डाला गया तो दस हजार हिंदू अपने प्राण देकर इसका विरोध करेंगे□ लेकिन जब तीसरे दिन रात में पुलिस की □क छोटी टुक□ी कब्जा लेने गई, तो उसे बंदूक चलाने को कौन कहे, लाठी-डंडा चलाने की भी नौबत नहीं आई, क्योंकि वहां केवल थोड़े से लोग इस कार्य में लगे थे जो केंद्रीय पुलिस बल को देखते ही वहां से चंपत हो ग□□

फैजाबाद के आयुक्त, जो केंद्र की ओर से इस विवादित स्थल के रिसीवर भी हैं, दबे मन से कहते हैं कि हां निर्णय तो हो गया है लेकिन अंतिम फैसला केंद्र को करना है, क्योंकि अयोध्या सर्किल □रिया इक्यूजीशन □क्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी विधि-सम्मत करार देकर केवल विवादित स्थल को उससे अलग किया है, यह भूमि केंद्र के अधीन है और फैजाबाद के मंडलायुक्त उसकी ओर से नियुक्त रिसीवर हैं□ अब केंद्र में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारू□ हैं और वे यह भी कहते हैं कि राम मंदिर बनाने का निर्णय संवैधानिक परिधि के भीतर ही होगा□

वर्तमान स्थिति में भी क्या वे अयोध्या को अति संवेदनशीलता के घेरे में रखना चाहते हैं और इसके पीछे इस आंदोलन के इतिहास की भांति कोई राजनीतिक कारण विद्यमान नहीं है? क्योंकि मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इन विवादित प्रश्नों को अपने अभियान का मुद्दा बनाया ही नहीं□ वे महंगाई, बेरोजगारी,

सुशासन, भ्रष्टाचार, विदेशों में जमा कालाधन और अच्छे दिन लाने के दावे को ही अपने चुनाव अभियान का आधार बना रहे थे।

सांप्रदायिक कट्टरता के बल पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को अधिक से अधिक तैंतीस प्रतिशत मत मिलता रहा, लेकिन इस चुनाव में राज्य में यह बढ़ कर बयालीस प्रतिशत लांघ गया जिसके कारण पुराने समीकरण ध्वस्त हो गए। लेकिन नई स्थितियों में कहीं इसकी आवश्यकता तो नहीं है कि यह संदेश दिया जाए कि राष्ट्र-द्रोहियों का खतरा कम नहीं हुआ है। इसलिए सुरक्षा के इन प्रयत्नों में उन्होंने धरती के साथ आकाश को भी ले लिया है। वहां की सुरक्षा के लिए सरकार तीन अरब रुपए से अधिक वार्षिक खर्च कर रही है लेकिन उसे नए प्रयत्नों की भी आवश्यकता है।

सुरक्षा के नाम पर अयोध्या को तीन भागों रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। अयोध्या के प्रमुख मंदिर, जिन्हें आस्था का केंद्र बताया जाता है, लगभग सभी येलो जोन में ही आते हैं, जहां पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और जहां राज्य और केंद्र के सुरक्षाबलों की सक्रिय चौकसी दर्शनार्थियों, आस्थावादियों और तीर्थयात्रियों के लिए साधक नहीं बल्कि बाधक ही बनती है। न राजनीतिक परिवर्तनों के बाद भी इसमें कोई ढील नहीं आई है। लेकिन राज्य का स्थायी शासक तो नौकरशाही है जिसे न शिगूफे अपनी आय और सुविधा के लिए आवश्यक लगते हैं। 'नो फ्लाइंग जोन' का फरमान वहां के मौजूदा सुरक्षा-खर्च में कैसे पूरा किया जाएगा, इसमें भी तो वृद्धि चाहिए!

यह कहा जा सकता है कि देश की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार सेना के खर्चे विवादों से परे हैं उसी प्रकार रामलला विराजमान की सुरक्षा को भी खर्च से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। यह बात दूसरी है कि पैंसठ वर्षों में कुछ ही बड़े और छोटे टकराव हुए हैं, फिर बीस वर्षों में कोई नया इतिहास इसमें नहीं जुड़ा है। साथ ही अब रामलला विराजमान को नुकसान पहुंचा कर या वहां हमला करके किन वृहत्तर उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, जो वर्तमान समीकरणों के विपरीत हो। शांतिपूर्ण समाधान की कौन कहे, अब तो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी भी यही कहते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि राममंदिर का निर्माण हो ही जाए। लेकिन कठिनाई यह है कि यह मंदिर निर्माण इस नाम पर होने वाली राजनीति को ही चोट पहुंचाएगा और उसकी हवा निकल जाएगी।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- https://twitter.com/Jansatta